*समृद्ध भारत के लिए समृद्ध राज्य**

डॉ. पूनम गुप्ता

कोलंबिया भारतीय अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, 2026 में उपस्थित होना मेरे लिए हर्ष का विषय है। मैं प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया को राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर भारत की संवृद्धि की गतिविधि से संबंधित मुद्दों पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ।

मेरा भाषण तीन भागों में है। सबसे पहले, मैं पिछले चार दशकों में भारत की आर्थिक संवृद्धि की गतिविधि की कुछ प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करूंगी और बताऊंगी कि यह आने वाले वर्षों के लिए क्या संकेत देती है। इसके बाद, मैं विभिन्न राज्यों की संवृद्धि की गतिविधियों की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करूंगी। अंत में, मैं 2047 तक एक अत्यधिक समृद्ध अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने की हमारी महत्वाकांक्षा के लिए इन अवलोकनों से कुछ निष्कर्ष और निहितार्थ निकालूंगी।

1. पिछले चार दशकों में भारत की आर्थिक वृद्धि की गतिविधि की प्रमुख विशेषताएं

भारत की आर्थिक वृद्धि में 1980 के दशक की शुरुआत से लगातार तेजी आई है। औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 1980 के दशक में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 1990 के दशक में 5.8 प्रतिशत हुई, जो 2000 के दशक में और बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई, 2010 के दशक में 6.6 प्रतिशत तक पहुंची और सबसे हाल के चार वर्षों की अवधि में 7.7 प्रतिशत तक पहुंच गई (सारणी 1)।

प्रति व्यक्ति आय में यह तेजी और भी अधिक स्पष्ट है (चार्ट 1)। 1981 में लगभग 274 अमेरिकी डालर और 1991 में 306 अमेरिकी डालर से, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2024 में लगभग 2700 अमेरिकी डालर हो गई है, जो कि लगभग दस गुना वृद्धि है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जबकि शुरुआत में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना होने में दो दशक से अधिक का समय लगा, इसके बाद के दो दशकों में यह लगभग पांच गुना बढ़ गई है, जो संवृद्धि की गति में एक स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव को इंगित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अक्टूबर 2025 के विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में किए गए अनुमानों के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय के 2025 में 2818 अमेरिकी डालर, 2026 में 3051 अमेरिकी डालर और 2030 में 4346 अमेरिकी डालर तक बढ़ने का अनुमान है।

सारणी 1: जीडीपी वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि

	वार्षिक औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)	वार्षिक औसत वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वृद्धि (प्रतिशत)
1980-81 से 1989-90	5.7	3.5
1990-91 से 1999-2000	5.8	3.7
2000-01 से 2009-10	6.3	4.6
2010-11 से 2019-20	6.6	5.2
2022-23 से 2025-2026*	7.7	6.7

टिप्पणी: 1. *: 2020-21 और 2021-22 के कोविड वर्षों को छोड़कर।
2. डेटा आधार वर्ष 2011-12 के लिए है।

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)। 2011-12 आधार वाली बैक सीरीज़ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली रिसर्च फाउंडेशन (ईपीडबल्यूआरएफ़), https://epwrfits.in/index.aspx से ली गई है (अंतिम बार 10 अप्रैल, 2026 को एक्सेस किया गया)।

जनसंख्या वृद्धि में गिरावट ने भी प्रति व्यक्ति आय में तेज संवृद्धि में योगदान दिया है। भारत की जनसंख्या वृद्धि, जो एक समय वैश्विक औसत से काफी अधिक थी, लगातार मंद हुई है और लगभग 2014 से वैश्विक स्तर के अनुरूप हो गई है, जिससे प्रति व्यक्ति आधार पर लाभ बढ़े हैं।

भारत ने तेज संवृद्धि और समष्टि आर्थिक स्थिरता का एक बेहतर चक्र प्राप्त कर लिया है। समष्टि आर्थिक स्थिरता का प्रतिबिंब मुद्रास्फीति, चालू खाता शेष, राजकोषीय स्थिति, ऋण की गुणवत्ता और वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य, सहित अन्य क्षेत्रों में स्थायी और आघातसहनीय परिणामों में देखा जा सकता है। प्रमुख समष्टि आर्थिक परिणाम, विशेष रूप से संवृद्धि (समग्र और क्षेत्रवार) और मुद्रास्फीति, मोटे तौर पर कम अस्थिर हैं और एक संकीर्ण, अधिक पूर्वानुमेय सीमा में चलते हैं।

मुद्रास्फीति में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप विकसित

* श्रीमती पूनम गुप्ता, उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 अप्रैल, 2026 को कोलंबिया विश्वविद्यालय के राज सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में आयोजित 'कोलंबिया इंडियन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2026' में दिया गया भाषण। आशीष थॉमस जॉर्ज, सोमनाथ शर्मा और शिवम द्वारा प्रदान किए गए इनपुट्स के उनका आभार व्यक्त किया जाता है।

[1] यह खंड गुप्ता (2026) पर आधारित है।

चार्ट 1: भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की दर जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना में तेज़ी से बढ़ी है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर में कमी का भी योगदान रहा है।

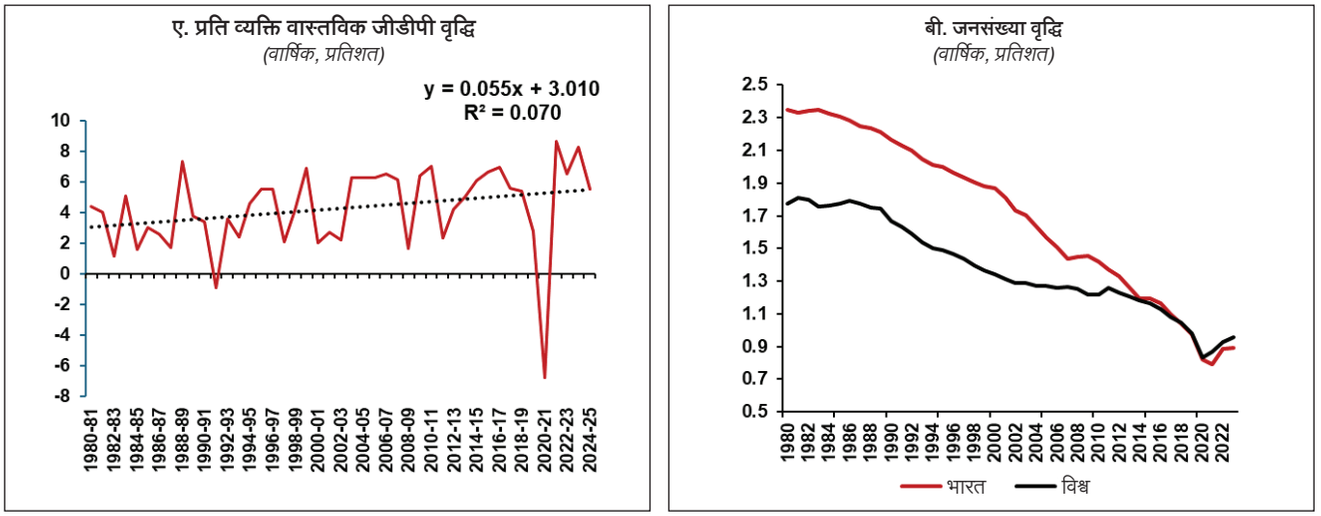

स्रोत: एनएसओ, विश्व बैंक और स्टाफ गणनाएँ।

अर्थव्यवस्थाओं और अन्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मुद्रास्फीति का अंतर संकुचित हुआ है।

भारत का दशकीय औसत चालू खाता घाटा 1990 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.5-2.2 प्रतिशत की मध्यम सीमा में बदलता रहा है और हाल के वर्षों में यह मामूली बना हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र में एक संरचनात्मक बदलाव आया है—तुलन पत्र में सुधार के एक दशक लंबे चरण के बाद, आज बैंक ऐतिहासिक रूप से और अपने समकक्षों की तुलना में काफी मजबूत और बेहतर पूंजीकृत हैं।

राजकोषीय मोर्चे पर, हालांकि कोविड-19 के दौरान घाटे और ऋण के स्तर में वृद्धि हुई थी, भारत पुनः समेकन के मार्ग पर लौट आया है, जिसका स्पष्ट फोकस मध्यम अवधि में घाटों को कम करने और ऋण को स्थिर करने पर है। राजकोषीय परिणामों की गुणवत्ता को बढ़ाने पर एक विशिष्ट ध्यान दिया गया है, जिसमें पूंजीगत व्यय की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव शामिल है, जिससे अर्थव्यवस्था की संवृद्धि क्षमता मजबूत हुई है (भारत सरकार, 2026)।

[2] भारत का सार्वजनिक ऋण टिकाऊ बना हुआ है। जैसा कि आइकनग्रीन, गुप्ता और अहमद (2024) द्वारा उल्लेख किया गया है, इसकी संरचना—मुख्य रूप से घरेलू, दीर्घावधि और रुपया आधारित—रीलोवर और मुद्रा जोखिमों को कम करती है, और अधिकांश धारणाओं के तहत, ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात में धीरे-धीरे गिरावट आने की उम्मीद है।

इन बेहतर परिणामों का श्रेय मजबूत नीतिगत फ्रेमवर्क और चुस्त नीतिगत प्रतिक्रियाओं को जाता है। भारत के नीतिगत फ्रेमवर्क लगातार विकसित हुए हैं और आज वे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाते हैं, जबकि घरेलू वास्तविकताओं में दृढ़ता से जड़े हुए हैं। राजकोषीय नीति में, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ़आरबीएम) फ्रेमवर्क ने राजकोषीय प्रबंधन के लिए नियम-आधारित मार्ग प्रदान किया है, जबकि कोविड और अन्य बाहरी घटनाओं जैसे आघातों के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए लचीलापन बनाए रखा है। कर नीति में, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) जैसे सुधारों ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया है और अनुपालन में सुधार किया है।

मौद्रिक नीति में, 2016 में पेश की गई लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) फ्रेमवर्क ने मुद्रास्फीति को कम किया है, मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर किया है, समष्टि आर्थिक अस्थिरता को घटाया है और नीतिगत विश्वसनीयता को बढ़ाया है। व्यापक वित्तीय क्षेत्र में, मजबूत बैंकिंग पर्यवेक्षण, बेहतर पूंजी मानदंडों और वित्तीय बाजारों में व्यापक विनियामक सुधारों ने प्रणाली की आघातसहनीयता को मजबूत किया है।

2. राज्यों में आर्थिक विकास के मार्ग की प्रमुख विशेषताएँ

राज्य पहले की तुलना में अधिक समृद्ध हो गए हैं। भारत की संवृद्धि की कहानी व्यापक समृद्धि से युक्त है, जिसमें पिछले

दो दशकों में प्रत्येक राज्य ने प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो यह इंगित करता है कि प्रगति केवल कुछ राज्यों या क्षेत्रों तक सीमित न रहकर संपूर्ण देशव्यापी रही है।[3] यह अमेरिकी डॉलर के मूल्यों में ही नहीं, बल्कि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित स्थिर रुपये के मूल्यों में भी देखा गया है।

पिछले दो दशकों में, राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय चालू अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में लगभग पांच गुना और स्थिर रुपये के संदर्भ में तीन गुना से अधिक बढ़ गई है, जो भारत की दीर्घकालिक आय में वृद्धि की शक्ति और निरंतर गति को रेखांकित करती है (सारणी 2)।

फिर भी, राज्यों में आय संवृद्धि की गति भिन्न-भिन्न रही है। पिछले दो दशकों में कुछ राज्य पांच से दस गुना अधिक समृद्ध हो गए हैं, जबकि अन्य ने लगभग तीन गुना की अधिक मामूली वृद्धि दर्ज की है। सापेक्ष प्रदर्शन का एक प्रबल सहसंबंधी कारक उनकी प्रारंभिक समृद्धि का स्तर है। अधिक समृद्ध राज्यों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर अपेक्षाकृत कम समृद्ध राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ा है। यह तथ्य कि अतीत में गरीब राज्यों की तुलना में धनी राज्यों ने अधिक समृद्धि का अनुभव किया है और यह प्रवृत्ति उलटी नहीं हुई है, इसका तात्पर्य यह है कि राज्यों में आय के स्तर में अभिसरण नहीं हुआ है।

इसके बावजूद, समय के साथ विचलन की सीमा काफी कमजोर हुई है (चार्ट 2ए, 2बी, और 2सी)। दूसरे शब्दों में, हाल के वर्षों में धनी और गरीब राज्यों के बीच संवृद्धि का अंतर संकरा हुआ है। 1990 के दशक के दौरान प्रारंभिक आय और बाद की संवृद्धि के बीच का संबंध सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण (5 प्रतिशत स्तर पर) था (चार्ट 2ए)। अगले दशक में यह संख्यात्मक रूप से छोटा और सांख्यिकीय रूप से कम महत्वपूर्ण (10 प्रतिशत स्तर पर, चार्ट 2बी) हो गया। पिछले दशक के दौरान, गुणांक में तेजी से गिरावट आई है; और प्रारंभिक आय तथा बाद की दशकीय संवृद्धि के बीच का संबंध अब महत्वहीन हो गया है (चार्ट 2सी)। विचलन में इस कमी को पिछले दशक के दौरान ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत कम आय वाले राज्यों के बेहतर प्रदर्शन सहित अन्य कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

समग्र रूप से, अतीत में धनी राज्यों द्वारा किया गया बेहतर प्रदर्शन न केवल उच्च आय संवृद्धि से, बल्कि धीमी जनसंख्य

[3] पिछले दशकों में इसके प्रभाव के साक्ष्यों के लिए पनगरिया (2010) देखें।

सारणी 2: 2024-25 से 2003-04 का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अनुपात

राज्य	नियत आईएनआर	वर्तमान अमेरिकी डॉलर
सिक्किम	6.0	11.4
तेलंगाना	4.5	7.9
कर्नाटक	3.9	6.7
तमिलनाडु	4.2	6.6
उत्तराखंड	3.9	6.1
आंध्र प्रदेश	3.5	5.9
अरुणाचल प्रदेश	2.7	5.8
ओडिशा	3.4	5.7
हरयाणा	3.3	5.6
गोवा	3.3	5.5
गुजरात	4.0	5.4
मिजोरम	4.3	5.3
राजस्थान	2.7	5.2
मध्य प्रदेश	2.9	5.2
बिहार	3.0	5.1
केरल	3.2	5.0
त्रिपुरा	3.9	4.9
असम	2.8	4.9
महाराष्ट्र	3.3	4.8
उतार प्रदेश	2.7	4.7
छत्तीसगढ	2.7	4.7
नगालैंड	3.0	4.6
हिमाचल प्रदेश	3.2	4.4
पश्चिम बंगाल	2.5	4.4
झारखंड	2.6	3.7
पंजाब	2.5	3.6
मणिपुर	2.1	3.5
मेघालय	2.2	3.3
औसत	3.3	5.4

टिप्पणी: 1. आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, सिक्किम, गोवा, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के लिए 2024-25 के आंकड़ों की जगह 2023-24 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है।

2. स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी (आईएनआर) 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित है;

3. औसत एक भारहीन (अनवेटेड) औसत है।

4. वर्ष 2003-04 से तेलंगाना के आंकड़े, जिसमें बैककास्टेड सीरीज़ शामिल है, ईपीडबल्यूआरएफ़ से प्राप्त किया गया था।

5. अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति आय की गणना, वर्तमान मूल्य प्रति व्यक्ति आय को संबंधित वार्षिक औसत विनिमय दर से विभाजित करके की गई थी।

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (ईपीडबल्यूआरएफ़ से प्राप्त); भारतीय अर्थव्यवस्था डेटाबेस (डीबीआईई) आरबीआई; और स्टाफ की गणनाएं।

चार्ट 2: आय के स्तर अभी तक समान नहीं हो रहे हैं, लेकिन असमानता बढ़ने की दर धीमी हो गई है

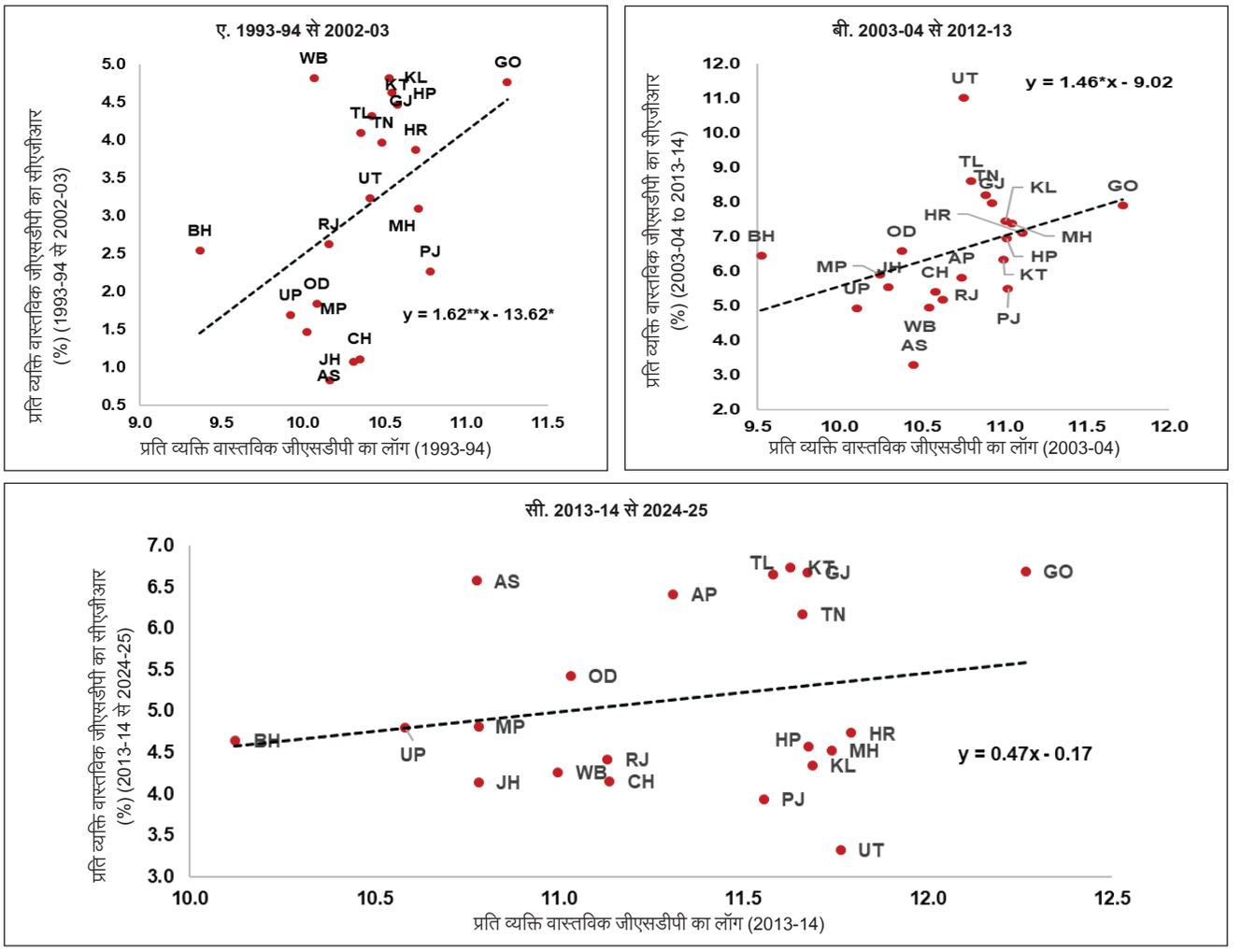

टिप्पणी: 1. चार्ट में राज्यों के लिए इस्तेमाल किए गए शॉर्ट नाम इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश (AP), असम (AS), बिहार (BI), छत्तीसगढ़ (CS), गोवा (GO), गुजरात (GU), हरियाणा (HR), हिमाचल प्रदेश (HP), झारखंड (JH), कर्नाटक (KA), केरल (KL), मध्य प्रदेश (MP), महाराष्ट्र (MH), ओडिशा (OD), पंजाब (PB), राजस्थान (RJ), तमिलनाडु (TN), तेलंगाना (TL), उत्तर प्रदेश (UP), उत्तराखंड (UK), और पश्चिम बंगाल (WB)। हर पैनल में ऑब्ज़र्वेशन की संख्या 21 है। 2. सीएजीआर का अर्थ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है; 3. *, **, *** क्रमशः 10%, 5% और 1% स्तरों पर सार्थकता को दर्शाते हैं। 4. झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए 1993-94 के वर्ष से, जिसमें बैककास्टेड श्रृंखला शामिल है, डेटा ईपीडब्ल्यूआरएफ़ से प्राप्त किया गया था। 5. गोवा और गुजरात के आंकड़े 2023-24 तक उपलब्ध है। 6. चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का अनुमान लगाने के लिए, निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है: सीएजीआर = ((अंतिम मान/आधार मान)1/t -1) * 100। उदाहरण के लिए, पैनल ए में, अंतिम मान 2002-03 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है। आधार मान 1993-94 में प्रति व्यक्ति आय है और T समय अवधि है, जो यहाँ 9 वर्ष है।
स्रोत: एमओएसपीआई (ईपीडब्ल्यूआरएफ़ से प्राप्त) और स्टाफ गणनाएँ।

वृद्धि से भी संचालित रहा है (सारणी 3)। मध्यम आय स्तर से ऊपर के राज्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की संवृद्धि दर अधिक रही है और साथ ही जनसंख्य वृद्धि दर धीमी रही है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में तेज संवृद्धि हुई है।

सारणी 3: राज्यों में औसत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि

(प्रतिशत)

	2003-04 से 2024-25 तक औसत वार्षिक वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि	2003-04 से 2024-25 तक औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि
माध्यिका से नीचे	6.8	1.4
माध्यिका से ऊपर	7.7	1.1

टिप्पणी: 1. आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, सिक्किम, गोवा, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के लिए 2024-25 के स्थान पर 2023-24 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।
2. 2003-04 में वास्तविक प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, राज्यों को माध्यिका से ऊपर या नीचे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। माध्यिका से ऊपर वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। माध्यिका से नीचे वाले राज्यों में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
3. बिना भारित औसत प्रस्तुत किया गया है।
4. तेलंगाना के लिए 2003-04 से आंकड़े, जिसमें पश्चगामित श्रृंखला शामिल है, ईपीडब्ल्यूआरएफ़ से प्राप्त किए गए थे।

स्रोत: एमओएसपीआई (ईपीडब्ल्यूआरएफ़ से प्राप्त) और स्टाफ गणनाएं।

यद्यपि राज्यों के बीच आय अभिसरण धीमी गति से हो रहा है, कई अन्य कल्याण संकेतक, विशेष रूप से प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, अधिक निश्चित रूप से अभिसरण की ओर अग्रसर हैं। पिछले अवधियों में, उदाहरण के लिए ग्रामीण उपभोग व्यय के मामले में, उपभोग संवृद्धि का प्रारंभिक उपभोग स्तर के साथ सकारात्मक संबंध पाया जाता था, जिसका अर्थ है कि धनी राज्यों में उपभोग संवृद्धि का स्तर उच्च था (चार्ट 3ए और 3बी)। हालाँकि, हाल की अवधि (2011-12 से 2023-24) में, यह संबंध उलट गया है: ऐतिहासिक रूप से कम उपभोग स्तर वाले राज्य अब तेज उपभोग संवृद्धि दर्ज कर रहे हैं, जो प्रारंभिक उपभोग स्तर पर एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण ऋणात्मक गुणांक द्वारा पुष्टि होती है (चार्ट 3सी)। यह भारतीय राज्यों में जीवन स्तर के वितरणात्मक अभिसरण की दिशा में एक सार्थक परिवर्तन को चिह्नित करता है।

उपभोग व्यय से परे, सामाजिक-आर्थिक कल्याण के कई अन्य आयाम भी अभिसरण की ओर अग्रसर हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा,

चार्ट 3: मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में अभिसरण

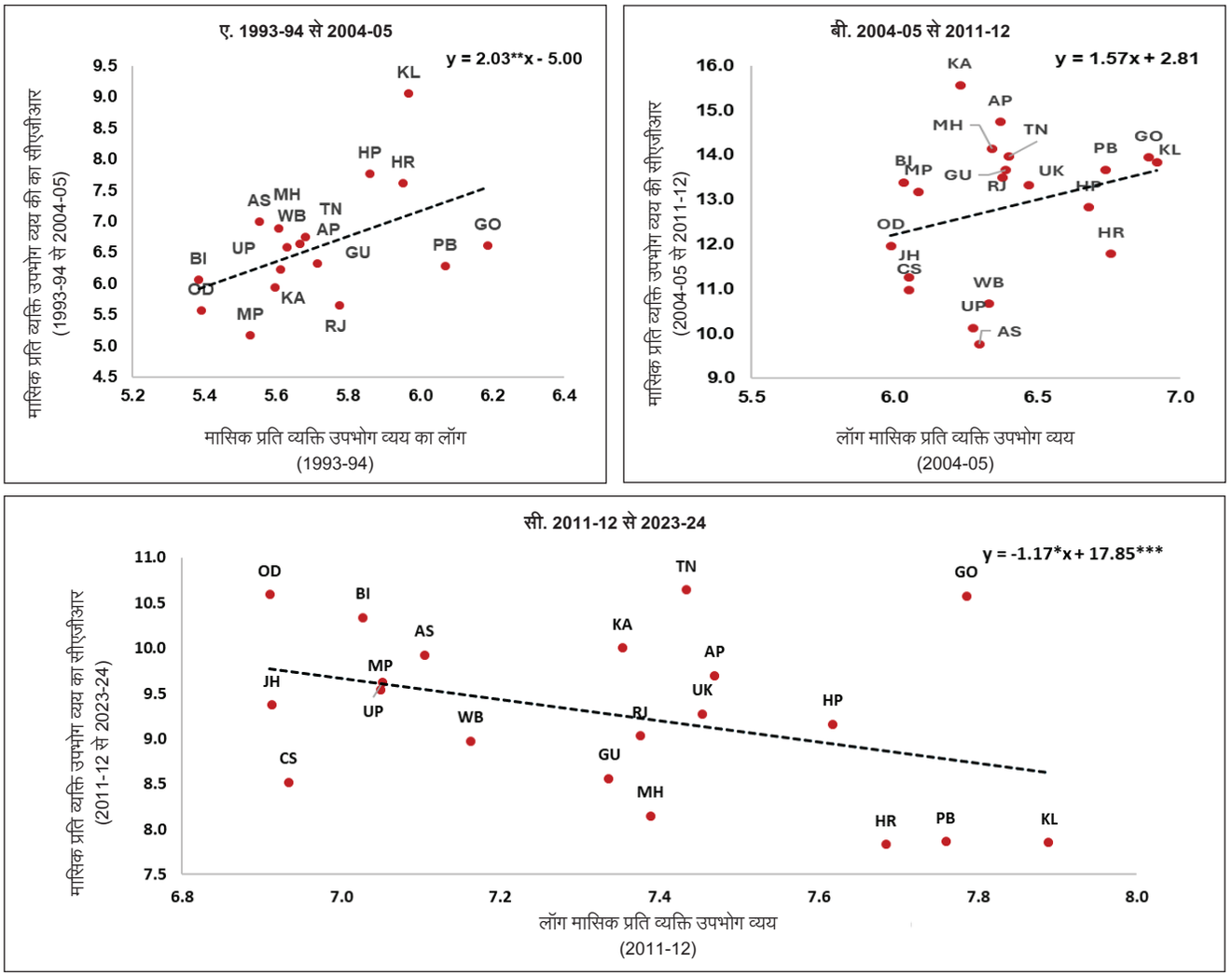

टिप्पणी: 1. *** क्रमशः 10%, 5% और 1% के स्तर पर महत्व को दर्शाते हैं। 2. सीएजीआर का मतलब चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है। 3. एमपीसीई ग्रामीण डेटा पर आधारित है। 4. पैनल 3ए और पैनल 3बी रिग्रेशन में यूनिफ़ॉर्म रेफरेंस पीरियड का इस्तेमाल करके इकट्ठा किया गया डेटा है। पैनल 3ए में 17 राज्य शामिल हैं, जो हैं: आंध्र प्रदेश (AP), असम (AS), बिहार (BI), गोवा (GO), गुजरात (GU), हरियाणा (HR), हिमाचल प्रदेश (HP), कर्नाटक (KA), केरल (KL), मध्य प्रदेश (MP), महाराष्ट्र (MH), ओडिशा (OD), पंजाब (PB), राजस्थान (RJ), तमिलनाडु (TN), उत्तर प्रदेश (UP) और पश्चिम बंगाल (WB)। पैनल 3b रिग्रेशन में, ऊपर बताए गए राज्यों के साथ-साथ कुछ और राज्य भी जोड़े गए, जैसे छत्तीसगढ़ (CS), झारखंड (JH) और उत्तराखंड (UK)। पैनल 3सी रिग्रेशन में मॉडिफ़ाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का इस्तेमाल करके इकट्ठा किया गया डेटा है।
स्रोत: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस), एमओएसपीआई (ईपीडब्ल्यूआरएफ़ से लिया गया) और कर्मचारियों की गणना।और स्टाफ गणनाएं।

जनसांख्यिकी, भौतिक अवसंरचना, बिजली तक पहुंच, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन और वित्तीय समावेशन से संबंधित संकेतक, राज्यों की प्रारंभिक आय के स्तर की परवाह किए बिना, सभी राज्यों में अधिक समानता की ओर अग्रसर हुए हैं। यह व्यापक अभिसरण संभवतः निरंतर नीतिगत प्रयासों, धनी राज्यों में संतृप्ति स्तर (जहाँ आगे की वृद्धि संख्यात्मक रूप से संभव नहीं है या प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से कठिन है), और गरीब राज्यों में बढ़ती मांग (जहाँ आय स्तर में वृद्धि का अनुभव हो रहा है) से संचालित है।

चार्ट 4 (4ए से 4एच तक) मुख्य परिणाम संकेतकों के एक चयन पर इन प्रवृत्तियों को चित्रित करते हैं। महिला साक्षरता दर (प्रति 100 महिलाओं पर साक्षरता दर) दशकों से लगातार बढ़ी है, जबकि प्रजनन दर (प्रति महिला जन्मों की संख्या) में क्रमिक गिरावट आई है (चार्ट 4ए और 4बी)। उन बच्चों का प्रतिशत जो कुपोषित नहीं हैं, में सार्थक सुधार हुआ है, जो 2005-06 में लगभग 62 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 70 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है (चार्ट 4सी)। शिशु उत्तरजीविता दर में भी दशकों से क्रमिक सुधार हुआ है (चार्ट 4डी)।

चार्ट 4: विकास संकेतकों में समानता

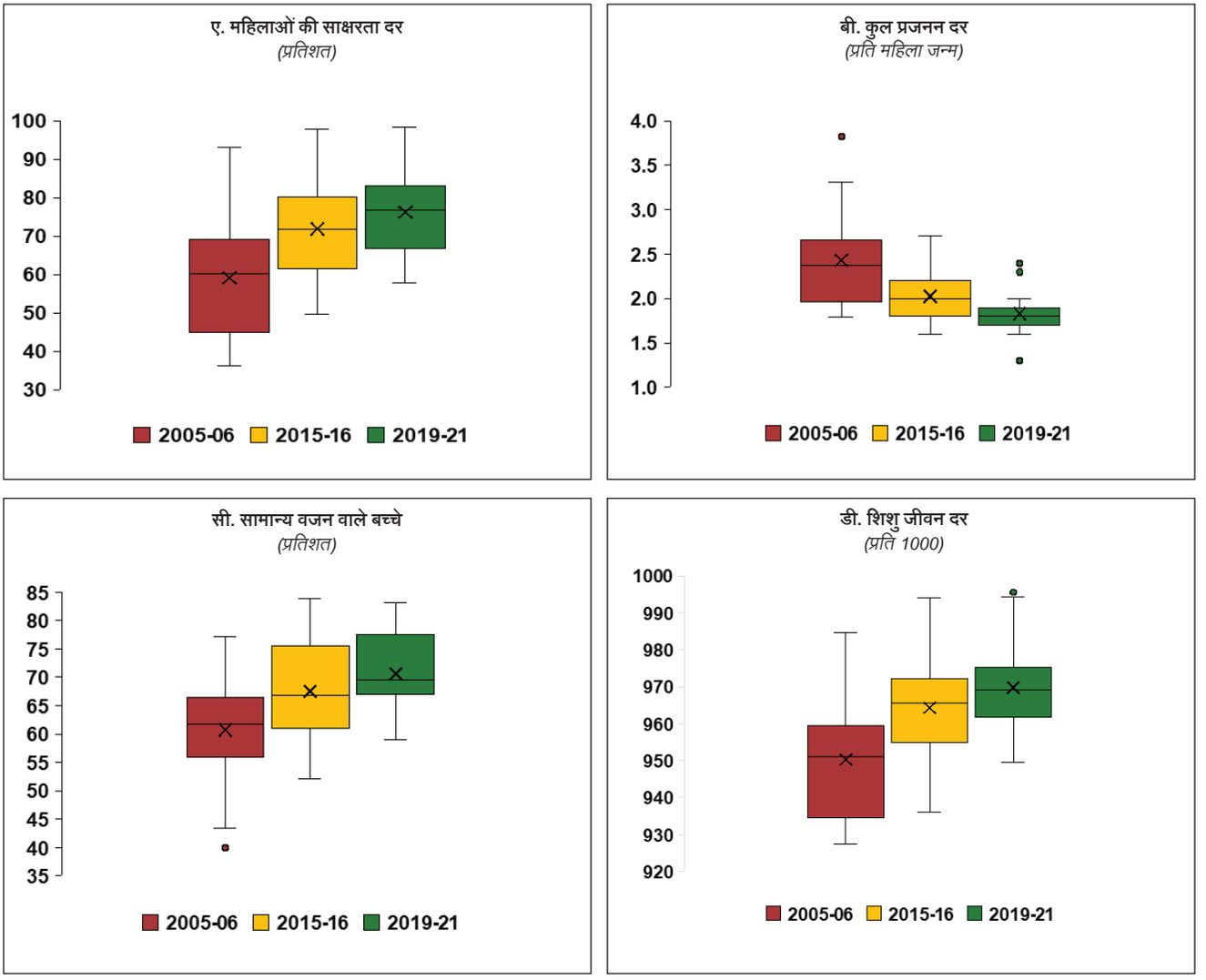

(Contd.)

चार्ट 4: विकास संकेतकों में समानता (जारी.)

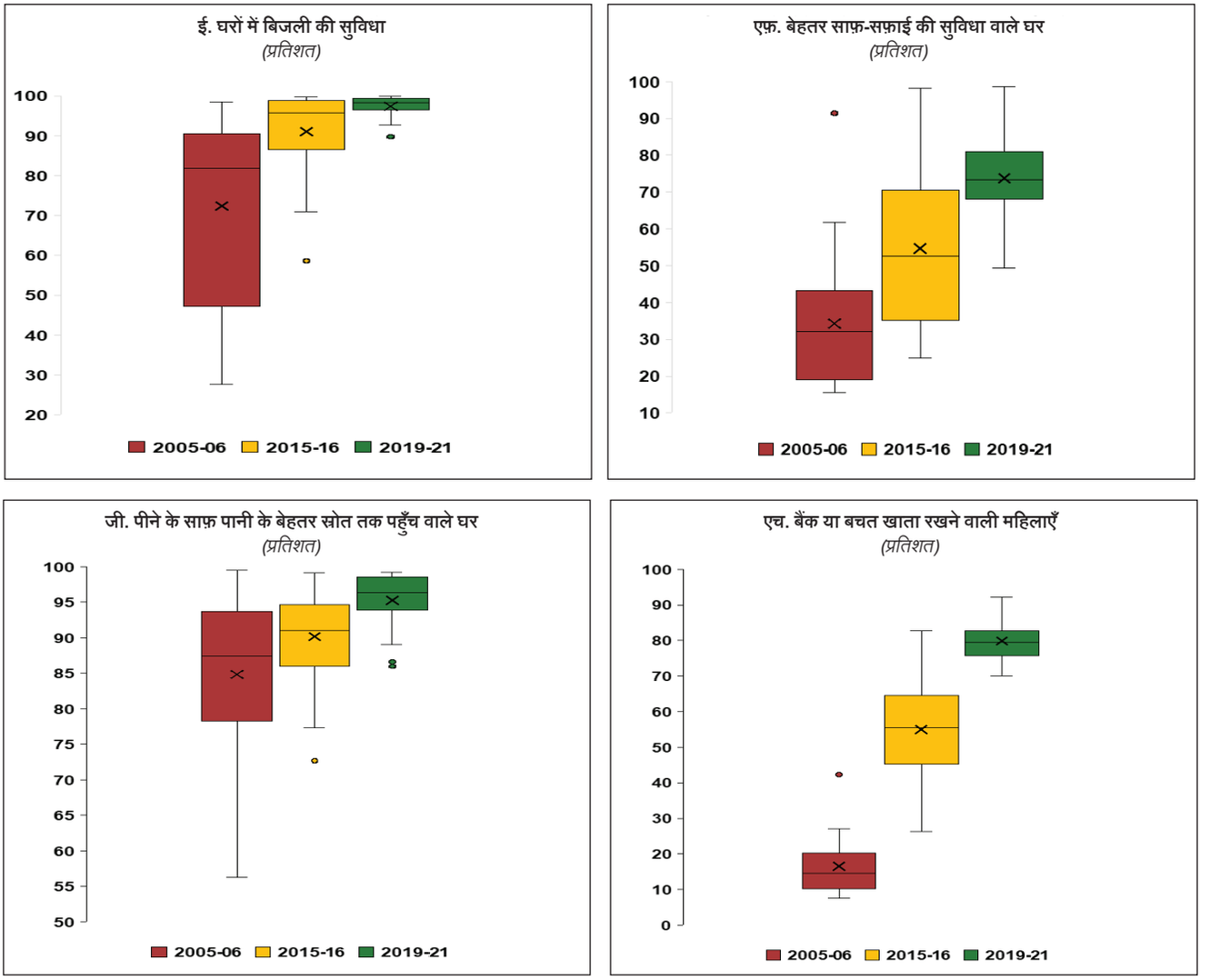

टिप्पणी: 1. बॉक्स इंटरक्वाटाइल रेंज (आईक्यूआर) का प्रतिनिधित्व करता है, जो तीसरे और पहले क्वार्टाइल (Q3-Q1) के बीच का अंतर है, और डेटा के बीच के 50% हिस्से को कवर करता है। औसत को क्रॉस ("x") से दर्शाया जाता है, जबकि माध्यिका को बॉक्स के अंदर की रेखा से दिखाया जाता है। व्हिस्कर 1.5 × IQR के भीतर के न्यूनतम और अधिकतम मानों तक जाते हैं। आउटलायर्स को व्हिस्कर के बाहर अलग से प्लॉट किया जाता है। 2. सामान्य वज़न वाले बच्चों का अनुपात 100 में से कम वज़न वाले बच्चों का प्रतिशत घटाकर निकाला जाता है। शिशु उत्तरजीविता दर, 1,000 में से शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्राप्त की जाती है। 3. कुल प्रजनन दर के लिए, 2005-06 में उत्तर प्रदेश (3.82) और गोवा (1.3); तथा 2019-21 में झारखंड (2.3) और उत्तर प्रदेश (2.4) में अपसामान्य (आउटलायर) देखे गए हैं। जिन बच्चों का वज़न कम नहीं है, उनके लिए 2005-06 में मध्य प्रदेश (40) में अपसामान्य (आउटलायर) देखा गया। शिशु जीवित रहने की दर के लिए, 2019-21 में केरल (995.6) अपसामान्य (आउटलायर) है। बिजली की सुविधा वाले घरों के लिए, 2015-16 में बिहार (58.6) और 2019-21 में उत्तर प्रदेश (89.8) में अपसामान्य (आउटलायर) देखे गए हैं। बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाले परिवारों के लिए, 2005-06 में केरल (91.4) एक अपवाद (आउटलायर) के रूप में देखा गया। बेहतर पेयजल स्रोत तक पहुँच रखने वाले परिवारों के लिए, 2015-16 में आंध्र प्रदेश (72.7) और 2019-21 में असम (86) के साथ-साथ झारखंड (86.6) अपवाद रहे। जिन महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है, उनके लिए 2005-06 में गोवा (42.3) एक अपवाद के रूप में सामने आया।
स्रोत: एनएफ़एचएस (ईपीडब्ल्यूआरएफ़ से प्राप्त)।

बिजली, स्वच्छता सुविधाओं और बेहतर पेयजल सुविधाओं तक घरों की पहुंच में वृद्धि के साथ, मूलभूत सेवाओं तक पहुंच पूरे राज्यों में काफी मजबूत हुई है (चार्ट 4ई, 4एफ़ और 4जी)। वित्तीय गहनकरण के संकेतकों में सुधार हुआ है; उदाहरण के लिए, भारत में बैंक खाते तक पहुंच वाली महिलाओं का प्रतिशत 2005-06 में 14 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 के दौरान लगभग 80 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 4एच)।

अभिसरण अन्य विकास संकेतकों जैसे लिंगानुपात (पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात), बच्चों में विटामिन ए कवरेज, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की घटना, स्टंटिंग (आयु के अनुसार कम लंबाई) और वेस्टिंग (लंबाई के अनुसार कम वजन), स्वच्छ ईंधन तक पहुंच, महिलाओं द्वारा फोन और घर/भूमि का स्वामित्व, तथा घरेलू स्वास्थ्य बीमा कवरेज में भी स्पष्ट है। इनमें से प्रत्येक संकेतक में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है,

जिससे राज्यों के बीच फैलाव कम हुआ है। यह कल्याणकारी परिणामों में व्यापक सुधार के साथ-साथ राज्यों में जीवन स्तर में बढ़ते अभिसरण को दर्शाता है। यहाँ हमने जो चित्रित किया है, वह केवल संकेतकों का एक उप-समुच्चय है। ऐसे कई अन्य संकेतक हैं जहाँ इसी प्रकार की घटना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

यह ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण है कि संवृद्धि और विकास के सभी सक्षमकारकों में अभिसरण सार्वभौमिक नहीं रहा है। आंकड़ों की सीमाएँ इसे पूर्ण आंकिक यथार्थता के साथ स्थापित करना कठिन बनाती हैं, लेकिन कुछ संरचनात्मक चरों के लिए अंतर-राज्यीय अभिसरण सीमित प्रतीत होता है, जिनमें राज्य अर्थव्यवस्थाओं में कृषि का हिस्सा, कृषि से बहार निकलने की गति, उत्पादकता संवृद्धि, पूंजी निर्माण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) के अंतर्वाह और बैंक ऋण संवृद्धि शामिल हैं। इन संकेतकों में देखे गए पैटर्न के अनुसार, संवृद्धि के कुछ चालक या सहसंबंधी अभी भी राज्यों में अपसरण दिखा रहे हैं।

यदि संवृद्धि की पिछली दरें बनी रहती हैं, तो 2047 तक कई राज्य "धनी" बन जाएंगे या धनी बनने के करीब पहुंच जाएंगे (समृद्धि की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अनुसार)। एक सरल काल्पनिक प्रयोग के रूप में, हमने पिछले दशक (2013-14 से 2024-25) में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (अमरीकी डॉलर के पदों में और पुनः स्थिर भारतीय रुपये में) की प्रत्येक राज्य की औसत वार्षिक संवृद्धि दर की गणना की है; और अगले दो दशकों तक उसी संवृद्धि दर के बने रहने की धारणा पर 2046-47 में आय स्तर का अनुमान लगाने के लिए इनका उपयोग किया है।

इस आधार पर, 2046-47 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय अमरीकी डॉलर के पदों में 4 गुना बढ़ने का अनुमान है। यह विस्तार व्यापक आधार वाला होने की उम्मीद है: मध्यम स्तर से ऊपर और नीचे दोनों तरह के राज्यों में महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किये जाने का अनुमान है, जिसमें मध्यम स्तर से नीचे के राज्यों द्वारा काफी गति प्रदान की जा रही है, जो भारत की संवृद्धि पथ की समावेशी प्रकृति को और मजबूत करती है (चार्ट 5)।

चार्ट 5: दशकों के दौरान प्रति व्यक्ति जीएसडीपी

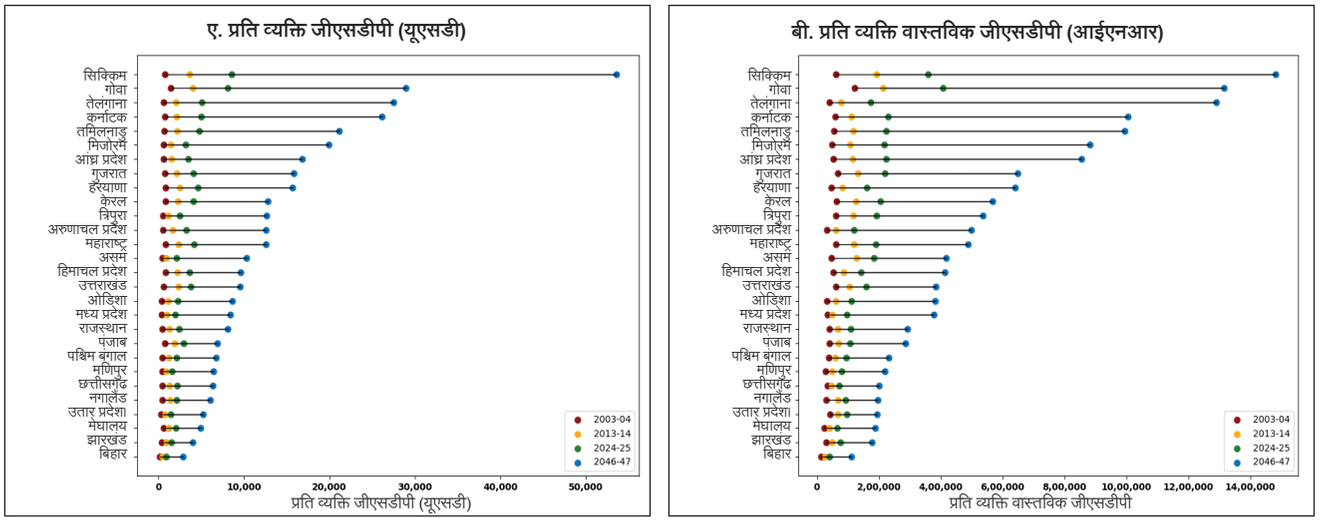

टिप्पणी: 1. आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, सिक्किम, गोवा, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के लिए 2024-25 के आंकड़ों की जगह 2023-24 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है; 2. तेलंगाना के लिए 2003-04 से डेटा (जिसमें बैककास्टेड सीरीज़ भी शामिल है) ईपीडब्ल्यूआरएफ़ से लिया गया था। 3. यूएसडी में प्रति व्यक्ति आय की गणना, मौजूदा कीमत पर प्रति व्यक्ति आय को संबंधित औसत वार्षिक विनिमय दर से विभाजित करके की गई थी।
4. 2046-47 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान लगाने के लिए, निम्नलिखित फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। $p^{2046-47} = p2024\text{-}25 * (1+g/100)^t$
*p*2046-47: 2046-47 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी
*p*2024-25: 2024-25 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी
g: 2013-14 से 2024-25 की अवधि के लिए औसत वार्षिक वृद्धि
t = समय अवधि, जो 22 साल है। जिन राज्यों के लिए 2023-24 का नवीनतम डेटा उपलब्ध है, उनके लिए समय अवधि 23 साल है।
स्रोत: एमओएसपीआई (ईपीडब्ल्यूआरएफ़ से लिया गया); भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) आरबीआई; और स्टाफ़ की गणनाएँ

[4] ऐसे परिवार जिनके कम से कम एक सदस्य के पास स्वास्थ्य बीमा का कवरेज है।

[5] यह सरल दृष्टिकोण संवृद्धि के स्रोतों या जनसंख्या वृद्धि दरों, सांकेतिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि दरों; या डिफ्लेटर की संबंधित प्रवृत्तियों के बारे में तटस्थ है।

3. 2047 तक एक अत्यधिक समृद्ध अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने की हमारी कवायद के लिए उपरोक्त अवलोकनों के निष्कर्ष और निहितार्थ

2047 तक समृद्धि के एक और उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए हालिया संवृद्धि पथों को बनाए रखना या उनसे बेहतर प्रदर्शन करना, उप-राष्ट्रीय स्तरों पर हमारे संवृद्धि फ्रेमवर्कों का विस्तार करने की मांग करेगा। नीतिगत प्राथमिकताएं स्वाभाविक रूप से राज्यों के स्पेक्ट्रम में भिन्न-भिन्न होंगी। मध्यम स्तर से ऊपर के राज्यों के लिए, ध्यान केंद्रित नवाचार और पैमाने, नियोजित शहरीकरण, वैश्विक और घरेलू प्रतिभा को आकर्षित करने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने, तथा व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और वित्त पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने पर होना चाहिए। मध्यम स्तर से नीचे के राज्यों के लिए, प्राथमिकताओं में कृषि में उत्पादकता को अनलॉक करना और इस क्षेत्र की पुनः कल्पना करना; कौशल निर्माण; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों में अधिक एकीकरण; अधिक उन्नत राज्यों की पूरकता करना (विशेष रूप से श्रम-गहन गतिविधियों में); राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण करते हुए विशिष्ट ताकतें विकसित करना; और तेज संवृद्धि का समर्थन करने के लिए राजकोषीय क्षमता को मजबूत करना शामिल हो सकता है।

वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्यों के पास उपलब्ध विशिष्ट नीतिगत भूमिकाओं का स्पष्ट स्वीकरण और अधिक प्रभावी उपयोग आवश्यक है।

अनेक समष्टि आर्थिक नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जाती हैं। इनमें मौद्रिक नीति; बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कवर करने वाला वित्तीय क्षेत्र विनियमन; इक्विटी और ऋण बाजारों तथा निजी इक्विटी का विकास; व्यापार, विनिमय दर और पूंजी खाता खुलेपन सहित बाह्य क्षेत्र से संबंधित नीतियां; और औद्योगिक तथा प्रतियोगिता नीति सहित अन्य शामिल हैं।

राज्य स्तर पर, उपलब्ध नीतिगत अवकाश और साधन भिन्न हैं, हालांकि वे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। राज्य सरकारें व्यापार करने में सुगमता के वातावरण को आकार देती हैं; भूमि और श्रम बाजार की स्थितियों का निर्धारण करती हैं; शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच; सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी; और अपने बजट का आवंटन आवर्ती और पूंजीगत व्यय के बीच तथा मेरिट और नॉन-मेरिट गतिविधियों के बीच करके सार्वजनिक वित्त की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। एक समग्र फ्रेमवर्क में इन सभी को सुदृढ़ करना प्रत्येक राज्य की समृद्धि की संवृद्धि दर और राष्ट्रीय औसत को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

समृद्धि भारत की महत्वाकांक्षा भी है और उसका भाग्य भी। अब मूल प्रश्न यह नहीं है कि क्या भारत समृद्ध होगा, बल्कि यह है कि यह समृद्धि कितनी शीघ्रता से, कितनी व्यापकता से और कितनी न्यायसंगत रूप से अपने राज्यों और जनता के बीच साझा की जाएगी।

आय में विचलन की गति काफी कमजोर पड़ी है, क्योंकि समृद्ध और गरीब राज्यों के बीच वृद्धि का अंतर लगातार कई दशकों से संकुचित हुआ है। इसी बीच, कल्याण और विकास के एक विस्तृत श्रेणी के संकेतकों—जैसे प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, साक्षरता, पोषण, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय समावेशन, और स्वास्थ्य तथा लिंग संबंधी परिणामों की एक श्रृंखला—में अभिसरण तेज और अधिक निर्णायक रहा है। पिछड़े राज्य पीछे से आगे बढ़ रहे हैं, और भारत में कल्याण का वितरण अधिक समान होता जा रहा है।

भविष्य की ओर देखें, तो यदि पिछले दो दशकों की वृद्धि प्रवृत्तियां बनी रहती हैं, तो 2046-47 तक औसत राज्य प्रति व्यक्ति आय उच्च-आय सीमाओं के निकट पहुंच सकती है। महत्वपूर्ण रूप से, अनुमान है कि माध्यिका से नीचे वाले राज्य इस विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जो भारत की वृद्धि की कहानी की व्यापक-आधारित प्रकृति को और सुदृढ़ करेगा। हालांकि, इस संभावना की पूर्ति और इसकी गति को त्वरित करने के लिए, राज्य-विशिष्ट वृद्धि रणनीतियों की ओर बढ़ना आवश्यक होगा, जो स्थानीय शक्तियों, संरचनात्मक वास्तविकताओं और विकास के अपने-अपने चरणों पर आधारित हों।

इसके लिए समग्र मूल्यांकन, समृद्ध संवाद, अधिक जागरूकता, राज्यों में विशिष्ट कार्रवाईयां, और एक-दूसरे से सीखते हुए अपनी मौजूदा शक्तियों का पूर्णतः लाभ उठाने और नए तुलनात्मक लाभों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

आइकनग्रीन, बैरी, गुप्ता, पूनम, और अहमद, आयशा। (2024)। भारत का ऋण दुविधा, इंडिया पॉलिसी फॉरम, खंड 20(1), पृष्ठ 1-62।

भारत सरकार (2026)। राजकोषीय विकास - विश्वसनीय समेकन के माध्यम से स्थिरता को सुदृढ़ बनाना, अध्याय 2, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, वित्त मंत्रालय।

गुप्ता, पूनम (2025)। आर्थिक आघातसहनीयता के लिए नीति फ्रेमवर्क: उभरते बाजारों और भारत का मामला (बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट शिखर सम्मेलन, मुंबई में संबोधन)।

गुप्ता, पूनम (2026)। भारत की संवृद्धि पर परिप्रेक्ष्य: पिछले चार दशकों से वर्तमान तक (केंद्र फॉर डेवलपमेंट स्टडीज का 14वां स्थापना दिवस व्याख्यान)।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2025)। विश्व आर्थिक आउटलुक, अक्टूबर।

पनागड़िया, अरविंद (2010)। संवृद्धि के मार्ग पर भारत: कोई राज्य पीछे नहीं, कोलंबिया प्रोग्राम ऑन इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज वर्किंग पेपर नं. 2010-1।

भारतीय रिज़र्व बैंक (2025)। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर।